

## MATTERS UNDER RULE 377

## (i) REPORTED LOSS OF FILE CONTAINING DOCUMENTS RELATING TO THE TIME-CAPSULE

श्री केशव राव खोंडगे (नासन्दा) : सदर साहब, मैं नियम 377 के द्वारा एक महमियत का सवाल उठाना चाहता हूँ।

कालपात्र के बारे में महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद के मुख्यालय से गायब हो चुके हैं। यह बड़ा गम्भीर मसला है। ये कागजात जिस दिन यह मसला लोक सभा में चर्चा के लिए आया उसी दिन गुम हो गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस पर स्टेटमेंट करने का साहस करें। जय कान्ति।

## (ii) REPORTED MOVE TO WIND UP THE JUTE CORPORATION OF INDIA AT CALCUTTA

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under Rule 377, I rise to draw the attention of the House to the reported move to wind up the Jute Corporation of India at Calcutta.

In the Economic Times of April 11, it was reported that the Government is contemplating to wind up the Jute Corporation of India with its headquarters at Calcutta and assign its function of price support operations to the Food Corporation of India which is supposed to have experience in similar operations. This will be a disastrous step not only for 1000 employees of the Jute Corporation of India but also for the jute growers in the jute growing States of West Bengal, Bihar, Assam, Arissa and Tripura for whose benefit the Jute Corporation of India was set up.

The Jute Corporation of India has already established about a hundred direct purchase centres to purchase jute from the growers. If the Corpo-

ration has not been able to give adequate relief to jute growers, if it has not been able to save them from exploitation, it is not because of some inherent fault in the Corporation but it is because of the incapacity of the present management and the wrong pricing policies taken up by successive Governments. The successive governments have always not paid the jute growers adequate price and the Agricultural Prices Commission has never been favourable to the jute growers. So, this extreme step to wind up the Jute Corporation is not called for and I want to request the Government not to consider this step at all.

## (iii) ADVERSE EFFECT OF POWER SHORTAGE ON AGRICULTURE AND INDUSTRIAL PRODUCTION

श्री बीरेन्द्र प्रसाद (नासन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सदन श्रीर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि :

“समस्त भारत में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। उत्पादन को जबरदस्त घटका कम रहा है। उत्पादन के अभाव में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, साथ साथ मजदूरों के सामने भी समस्या बढ़ी होती है। विशेष कर बिहार राज्य में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों में हताशता मचा है। जितने मेगावाट बिजली का उत्पादन है उसके ज्यादा बिजली विभाग ने बिजली देने का ऐसीमेंट कर रखा है। यद्यपि बिजली की क्षमता नहीं होती फिर भी उपभोक्ताओं से निम्नम बारन्टी ली जाती है जिससे उपभोक्ताओं में काफी जोश है। सरकार को इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिये कि उपभोक्ताओं को बिजली क्षमता की बारन्टी मिले। यदि बिजली क्षमता की बारन्टी नहीं है तो निम्नम बारन्टी